इंदौर की घटना के बाद भी नहीं जागी नगरपालिका, मटमैले, अशुद्ध पानी की हो रही सप्लाई

मप्र की मुम्बई कहे जाने वाले इंदौर घटना से नहीं चेता स्थानीय प्रशासन, जर्जर लाइनों से आज भी पहुंच रहा दुर्गंध युक्त पानी,लीकेज का सही सुधार न होने से गंदा एवं दुर्गन्धयुक्त पानी पहुंचता है सप्लाई लाइन में

▶ शहर मे कई जगह सप्लाई लाइनों के लीकेज से घरों तक पहुंचता है दुर्गंधयुक्त पानी।

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, मप्र की मुम्बई कहा जाने वाला सबसे स्वच्छ शहर मे शुमार इंदौर मे जब प्रदूषित पानी से लगभग 14 लोगों की मौंत को लेकर पूरे प्रदेश मे चर्चा आम है और शासन पूरे प्रदेश के सभी जिलों को पेयजल सप्लाई को लेकर कड़े दिशा निर्देश भी दिये हैं लेकिन इसका असर पन्ना जिले में नहीं देखने को मिल रहा है।

पन्ना नगर मे शायद ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहां की पाईपलाइनों में लीकेज न हो। बार बार सड़क एवं नालियों की खुदाई होने से पाइप लाइनों में टूट फूड हुई जिनका सही ढंग से सुधार न होने से लीकेज की समस्या बनी रही। और उन्हीं लीकेज से गंदी नालियों एवं सड़कों का पानी सप्लाई लाइनों से घरों में पहुंचता है जिससे मटमैला एवं दुर्गंध युक्त पानी कहीं कहीं पहुंच रहा है। लेकिन इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन आज भी गम्भीर नहीं दिखाई दे रहा है। इंदौर की घटना के बाद नगर पालिका एवं नगर परिषदों में निवास करवाने वाला आम नागरिक एवं उपभोक्ता इसलिये डरा हुआ है कि कहीं उसके साथ ही इंदौर जैसी घटना न हो जाय। जहां तक पन्ना की बात है तो यहां भी असर किसी न किसी मुहल्ले से खबर आती रहती है कि नल से आने वाला पानी दुर्गन्धयुत आ रहा है। कईबार तो यहां तक आरोप लगते हैं कि नल से आने वाली पानी में कीड़े तक आते हैं। फिर भी कई लोग ऐसे हें जो नल के पानी से ही जीवनयापन करते हैं। इसलिये स्थिति न केवल खतरनाक है अपितु शासन व प्रशासन के लिये चिन्ताजनक भी है। तकनीकी रूप से यह देखा जाना चाहिये कि नगरीय निकाय में पाईपलाईन के जिस नेटवर्क के माध्यम से पानी आपूर्ति किया जा रहा है वह सही है सुरक्षित है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेयजल वाली पाईप लाईन में मल जल युक्त सीवर लाईन का पानी प्रवेश कर रहा है जो उपभोताओं तक पहुच रहा है।

लीकेज इतने कि दिखती है व्यवस्था में अनेक कमियां:- जिस समय पानी की आपूर्ति शुरू की जाती है उस समय शहर में कई जगह पाईप लाईनों से लीकेज की स्थिति साफ दिखाई देती है। कहीं जलापूर्ति लाईन से पानी की तेज फबार सड़क में निकलता है तो कहीं सड़कों ने लीकेज के चलते पूरी सड़क पानी से गीली हो जाती है। इस तरह की स्थिति बताती है कि पानी लाईन में लीकेज है जहां पानी की आपूर्ति बंद होने और आसपास गंदा एवं प्रदूषित पानी का श्रोत होने अथवा सीवरेज की पाईप लाईन के खराब होने से उसका भी पानी पेयजल की लाईन में प्रवेश कर सकता है। किन्तु सुधार के नाम पर गंभीरता से काम नहीं होता। जब स्थिति गंभीर रूप ले लेती है तो प्रशासन व शासन को चिन्ता होती है। सिस्टम को खराब करने वाला कोई और होता है और बदनाम समूचे व्यवस्था को भुगतनी पड़ती है।

गरीब परिवारों के पास पेयजल के लिये जलापूर्ति ही विकल्प:- यह भी सही है कि नगरीय क्षेत्र में गरीब परिवार के लोगों के लिये पेयजल का विकल्प नल जल ही है। एक बड़ी आबादी इस पानी का उपयोग करती है। सक्षम लोगो के पास कई विकल्प होते हैं। जो नगर पालिका के पानी का उपयोग न करके प्राइवेट एजेंसियों के पानी की खरीदी कर लेते हैं। अथवा निजी ट्यूबबेल के माध्यम से प्यूरीफायर से पानी का उपयोग करते हैं। किन्तु गरीब परिवार के लोगों को देखा जा सकता है नाली में निकले हुये पेयजल के पाईप में अपने पात्रों में पानी भरकर घरों तक ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को शुद्ध पानी मिले यह सुनिश्चित होना चाहिये। केवल भाषणों एवं घोषणाओं मात्र से शुद्ध पानी नहीं मिल सकता। समय पर पानी के गुणवत्ता की जांच भी होनी चाहिये।

नल जल सिस्टम की तकनीकी जांच गंभीर से होना जरूरी- इंदौर की घटना के बार यह सवाल उठ रहा है कि नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र के नल जल सिस्टम की तकनीकी जांच गंभीरता से करवाये। इस बात की जांच होनी चाहिये कि किन मुहल्लों मे प्रदूषित पानी पहुच रहा है। जल गुणवत्ता की जांच एवं जनता से प्राप्त होने वाले फीडबैक के अनुसार जलापूर्ति सिस्टम की जांच की जानी चाहिये। चिन्ता इसलिये भी है कि जिस शहर को प्रदेश व देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जा रहा था। जिस शहर में सभी सुविधायें उत्कृष्टस्तर की बताई जा रही थी। जब उसी शहर में प्रदूषित पानी जनता को मिल रहा था तो अन्य शहरों में जहां न तो कोई व्यवस्था है और न ही निकायों के पास उतनी क्षमता वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिये उच्च स्तरीय तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाना चाहिये। इसके साथ ही उन कमजोरियों एवं खामियों को सुधारा जाना चाहिये जिनके माध्यम से प्रदूषित पानी के कारण संक्रमण होने या कोई घातक बीमारी होने की संभावनायें पाई जाती हों।

विकास के नाम पर हुए कई खतरनाक प्रयोग

शहर में देखा जाय तो विकास के नाम पर कई प्रयोग हो चुके हैं। जहां सड़कों को खोदकर कभी पानी की पाईप लाइने डाली गई, डाली गई। खुदाई के दौरान पूर्व से पड़ी लाईनों या पाईप लाईनों को छतिग्रस्त कर दिया गया। फिर उन्हें गंभीरता सुधारा तक नहीं गया। यही कारण है कि कई जगह पाईप लाईनों में लीकेज अकस्मात होना शुरू हो जाता था। किन्तु इसमें गंभीर स्थिति तो तब पैदा होती थी जब पेयजल आपूर्ति की लाईने प्रभावित होती थी और जलापूर्ति के समय पर मटमैला पानी, बदबूदार पानी, कीड़े मकोड़ों से युक्त पानी आपूर्ति होता था। पन्ना की जनता का यह सौभाग्य था कि पूर्व में इंदौर की तरह कोई घटना नहीं हुई। इस तरह की स्थिति बताती है कि पानी लाईन में लीकेज है जहां पानी की आपूर्ति बंद होने और आसपास गंदा एवं प्रदूषित पानी का श्रोत होने अथवा सीवरेज की पाईप लाईन के खराब होने से उसका भी पानी पेयजल की लाईन में प्रवेश कर सकता है। किन्तु सुधार के नाम पर गंभीरता से काम नहीं होता। इसलिये इंदौर की घटना के बाद केवल नगर पालिका क्षेत्र पन्ना अपितु समूचे नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति की लाईनों को दुरूस्त किया जाना चाहिये।

दक्षिण पन्ना की पवई रेंज में शिकारी गिरफ्तार, फंदे जब्त

नवभारत न्यूज

पवई/ पन्ना 5 जनवरी, दक्षिण पन्ना वनमण्डल में शिकारियों के विरुद्ध निरंतर चल रहे अभियान के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र पवई में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई।

नियमित गश्ती के दौरान ग्राम हथकुरी क्षेत्र में वन सीमा से लगे खेत की बागड़ की जांच के समय क्लच बॉयर के तार से बने अवैध फंदे बरामद किए गए। प्रारंभिक संदेह के आधार पर की गई जांच में सामने आया कि उक्त खेत में रहने वाले भाईलाल आदिवासी, पिता बोड़ा आदिवासी द्वारा पूर्व में जंगली सुअर का शिकार किया गया था तथा वह आगे शिकार की तैयारी में था। वन अमले ने त्वरित

कार्रवाई करते हुए आरोपी भाईलाल आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे उपजेल पवई भेजा गया। इस कार्यवाही में वन परिक्षेत्र अधिकारी पवई नितेश पटेल के नेतृत्व मे गठित टीम का योगदान रहा।

कलेक्टर ने 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए घोषित किया दो दिवस का अवकाश

पन्ना 5 जनवरी, कलेक्टर ऊषा परमार ने वर्तमान में तापमान में गिरावट व ठण्ड के कारण एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत पन्ना जिले के समस्त विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 6 एवं 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों सहित केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, अनुदान प्राप्त विद्यालय व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में दो दिवस का अवकाश रहेगा, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पूर्व निर्धारित समयानुसार लगेंगी तथा परीक्षाएं भी समय सारणी अनुसार संचालित होंगी। शाला के समस्त शिक्षक व अन्य कर्मचारी समय पर विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय के अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, सहा.जि.लोक अभि.अधि. रोहित गुप्ता ने बताया कि, दिनांक 03 अगस्त 2020 के प्रात: 9:45 बजे फरियादी देवी सिंह राजगौंड़ ने इस आशय की लेख करायी कि दिनांक 02 अगस्त 2020 को करीब शाम 05:00 बजे उसके पिता प्रहलाद सिंह हीरापुर पन्ना से हमारे घर औरैया आए तथा गजराज सिंह बोले कि तुमने नसीम भाईजान पन्ना वालों के पैसे अभी तक वापस क्यों नहीं किए तो इस पर गजराज ने कहा कि अभी उसके पास पैसे नहीं है वह मजदूरी करके पैसे वापस कर देगा।

इसी बात पर उसके पिता प्रहलाद तथा भाई गजराज का विवाद हो गया था, रात्रि लगभग

1:00 बजे उसे गाली-गलौज की आवाज सुनायी दी। आवाज सुनकर वह तथा उसकी मां एवं भाई विकम आए। देखा कि पिता प्रहलाद व उनके साथ हीरापुर टपरियन पन्ना का राजेन्द्र सिंह यादव था। राजेन्द्र सिंह ने जान से मारने की नीयत से बंदूक से गजराज पर फायर किया, जब उसने राजेन्द्र सिंह को ललकारा तो राजेन्द्र सिंह मादरचोद गुड़वा आओ तुम्हे भी देखते है तब राजेन्द्र सिंह ने उसे भी जान से मारने की नियत से बंदूक से उस पर फायर किया तो वह बचकर अंधेरे की तरफ भाग कर छिप गया। हमने गजराज को देखा तो उसके दाहिने तरफ गोली लगने से खून बह रहा था तथा वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी।

गजराज को मोटर साइकिल में बैठाकर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल अजयगढ़ लेकर आये, जहां डॉक्टर साहब ने गजराज को देखकर बताया कि इसकी मृत्यु हो गयी है। आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना अजयगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय प्रदीप कुशवाह, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी (पी.ए.) एक्ट पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव द्वारा की गयी। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए मृतक गजराज के संबंध मे न्यायालय द्वारा आरोपी- राजेन्द्र सिंह यादव को धारा 302 भादंसं. में आजीवन कारावास, 1000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड, धारा 201 भादंसं. में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। एवं देवी सिंह की हत्या के प्रयास के अपराध में राजेन्द्र सिंह को धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में आयी हुई साक्ष्य के आधार पर मृतक के पिता प्रहलाद सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया।

कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, कलेक्टर ऊषा परमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में लंबित विभागवार शिकायतों व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत बेहतर रैंकिंग के संबंध में निरंतर रूप से अपेक्षित प्रयास कर स्थिति में सुधार लाने तथा तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रकरणों के उचित निराकरण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा

कि समस्त विभाग ए श्रेणी रैंक के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करें। समाधान ऑनलाइन के चयनित विषयों के निराकरण की समीक्षा सहित टीएल और जनसुनवाई पत्रों के त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए गए। साथ ही शासन के महत्वपूर्ण पत्रों का भी समय सीमा में विधिवत तरीके से निराकरण के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने टीएल बैठक में आरटीओ को निरंतर रूप से वाहनों की फिटनेस व अन्य जरूरी जांच के लिए निर्देशित किया। साथ ही हेलमेट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन कराने तथा पेट्रोल पम्प पर बगैर हेलमेट के पेट्रोल विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के पुन: निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले में धान भण्डारण व परिवहन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान निकायवार खाद्यान्न आवंटन के बारे में भी पूछा और प्रत्येक माह की 20 तारीख तक शत प्रतिशत राशन वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। समस्त एसडीएम एवं तहसीलदार को स्वयं एवं पटवारी व राजस्व निरीक्षक के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण, पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों के बेहतर उपचार व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में भी सतत निरीक्षण व मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। इस मौके पर खजुराहो में आगामी हीरा नीलामी की कार्रवाई संपन्न कराने के संबंध में भी आवश्यक तैयारी के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर ने गत कलेक्टर-कमिश्नर कांन्फ्रेंस के विभागवार बिन्दुओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा सहित पन्ना की भांति अन्य नगरीय निकायों में गीता भवन के लिए जमीन के चिन्हांकन, विकासखण्डवार समग्र आईडी की प्रगति, आयुष्मान कार्डधारी गंभीर मरीजों को एयर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ प्रदान करने, आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की जांच सहित शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक प्रयास के निर्देश भी दिए।

जर्जर भवन में संचांलित है श्रम विभाग का कार्यालय

कार्यालय के सामने पानी ठहरने से दलदल में हो जाता है तब्दील

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, जिला पंचायत परिसर में संचालित श्रम विभाग का कार्यालय एक जर्जर भवन में संचांलित हो रहा है। वहीं प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में जलभराव के कारण कार्यालय के सामने पानी भर जाने से निकलना मुश्किल हो जाता है।

कार्यालय की पूरी बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है। जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। विभागीय मंत्री के जिले में कार्यालय की यह बदहाली चिंता का विषय है। इससे डीईओ कार्यालय व जिला पंचायत कार्यालयों के आसपास का पूरा पानी सिमटकर श्रम विभाग के गेट में रुक जाता है। इसके आगे जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा पानी कार्यालय के बाहर आकर ठहर जाता है। इससे कार्यालय के प्रवेश द्वार की स्थिति तालाब जैसी हो जाती है।

कबाड़ हुआ इकलौता वाहन

श्रमपदाधिकारी और विभागीय अधिकारियों के उपयोग के लिए पूर्व में श्रम विभाग को एक वैन दी गई थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यह विभाग के कार्यालय के बाहर महीनों से खुले में खड़ी है। यह चलने योग्य नहीं है और विभाग को अभी तक दूसरा वाहन नहीं मिला है। इससे यहां पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का सरकारी कामकाज के लिए निजी वाहनों का उपयोग करना पड़ता है य फिर निजी वाहन किराए पर लेना होता है। विभाग की बदहाली की ओर जिला प्रशासन को ध्यान ही नहीं दे रहा है विभाग के मंत्री भी शायद ही कभी इस कार्यालय तक आए हों। बाहर से इस कार्यालय की हलात तो किसी कबाड़ हुए भवन जैसी लगती है।

खरीदी केंद्रों में किसानों का शोषण, गुणवत्ता के नाम पर मनमानी वसूली

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, धान खरीदी में जहां किसानों की भीड़ अधिक जमा हो रही है वहां तौल से लेकर गुणवत्ता परीक्षण आदि में व्यापक अनियमितता व मनमानी की जा रही है। एक तरफ कई किसान हैं जो इस भीषण ठण्ड में कई दिनों तक तौल का इंतजार करते बैठे रहते हैं वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों से सौदा हो जाता है उनका नम्बर पहले आ जाता है।

इस तरह से किसानों के साथ अबैध वसूली भी हो रही है। किन्तु जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई नही करते। यदि कोई किसान ऐसे अधिकारियों को फोन से भी सूचना देना चाहता है तो उनके फोन ही नहीं उठते। इसका मतलब है कि खरीदी व्यवस्था में जमकर मनमानी की जा रही है।

सर्वेयरों की चल रही वसूली:- देखा जा सकता है कि खरीदी केन्द्रों में पदस्थ सर्वेयरों की स्थिति शर्मनाक है। उनका काम ईमानदारी के साथ सर्वे करने का हे। किन्तु जानबूझकर और गलत मानसिकता से किसानों से वसूली करना। किसानों को भ्रमित कर धान को खराब बताना फिर वसूली करना। पैसे मिल जाने के बाद उसी धान को सही बता देना यह सब सर्वेयरों के द्वारा किया जा रहा है। किसानों की धान की गुणवत्ता का परीक्षण करने वाले सर्वेयर द्वारा नकद राशि की मांग की जाती है। जो किसान यह राशि नहीं देता उसका नम्बर ही नहीं आता, उसकी धान की तौल ही नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में किसान द्वारा स्लाट बुक करने के बाद भी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इससे समझा जा सकता है कि खरीदी केन्द्र में किस तरह से मनमानी की जा रही है।

मात्रा से अधिक तौल एवं प्रति बोरा वसूली अलग:- यहां यह भी देखा जा रहा है किकिसानों से 41 किलो 500 ग्राम प्रति बोरा धान की तौल की जाती है जबकि बताया गया है कि साढें चालिस किलो ही तौल प्रति बोरा किये जाना चाहिये। इस तरह से प्रतिबोरा लगभग एक किलो अधिक तौल की जा रही है। किसानों से प्रति बोरे के मान से पांच रूपये तौलाई भी वसूली जा रही है। जबकि बताया जाता है कि तौलाई की राशि किसानों से वसूल नहीं की जानी चाहिये। इसका व्यय खरीदी करने वाली एजेंसियों को उठाना चाहिये। क्योकि इसके बदले उन्हें सरकार से कमीशन मिलता है और व्यवस्था के लिये भी आवश्यक राशि मिलती है। बावजूद इसके खरीदी केन्द्र में मनमानी तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा है। मौके पर जहां किसानों की जानकारी के लिये बैनर लगाये जाने चाहिये तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होना चाहिए उसका भी अभाव यहां देखा जाता है। इसलिये सब कुछ नियमों व निर्देशों के विपरीत हो रहा है। इसके बाद भी किसानों की मजबूरी है कि उन्हें अपनी उपज की बिक्री करनी है इसलिये वे अपने नम्बर का इंतजार करते बैठे रहते हैं।

अधिकांश केन्द्रों में मनमानी

लगभग सभी खरीदी केन्द्रों की स्थिति मनमानीपूर्ण है। जहां किसानो की संख्या अधिक है और जहां धान का उत्पादन अधिक होता है। खरीदी के पहले जब तैयारियां होती हैं तो किसानों को बताया जाता है कि सब कुछ नियमो व निर्देशों के नुसार ही होगा। केन्द्रों की व्यवस्था को देखने व निगरानी करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता है। बावजूद इसके देखा जाता है कि जब खरीदी प्रारंभ हो जाती है तो किसानों के साथ भेदभाव, मनमानी वसूसी लेकरउनका आर्थिक शोषष खरीदी केन्द्रों में शुरू हो जाता है। यही कारण है कि खरीदी के दौरान ओर उसक पश्चात भी कई किसानो को परेशान होना पड़ता है। यदि खाते में राशि नहीं पहुचती तो उसके सुधार को लेकर भी कइ किसानों को कई दिनो तक भटकना पड़ता है। यही कारण है कि फिर सीएम हेल्पलाईन से लेकर विभिन्न माध्यमों से शिकायतों की संख्या भी बढ़ती है। जिससे व्यवस्था को लेकर सवाल उठते है।

शासकीय मेडिकल कॉलेज की जगह पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज से खुश नहीं हैं जिलेवासी

पन्ना 5 जनवरी, जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा के बाद जहां आम जनता मे खुशी की लहर दौड गई थी कि अब जिलेवासियों के पड़ोसी जिलों में अच्छे इलाज के लिए नहीं जाना पडेगा। लेकिन उनके अरमानों में उस समय पानी फिर गया जब पता चला कि शासकीय मेडिकल कॉलेज की जगह पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जाने से लोगों को निराश कर दिया है। लोगों का कहना हैं कि जिले की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है।

मकर संक्रांति मेला की आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में हुई बैठक

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, पन्ना जिले के विभिन्न स्थानों पर आगामी 14 जनवरी, मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले मेलों में श्रद्धालुओं व जनसामान्य की आवश्यक सुविधाओं के मद्देनजर जरूरी तैयारियों के संबंध में कलेक्टर ऊषा परमार की अध्यक्षता में सोमवार को बैठक आयोजित की गई।

जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई मकर संक्रांति मेला की तैयारी बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों

के साथ जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मंदिरों में साफ-सफाई व्यवस्था व अनुमानित भीड़ के दृष्टिगत यातायात व पार्किंग एवं सुरक्षा व पेयजल व्यवस्था इत्यादि के संबंध में निर्देशित किया गया।

बैठक में जानकारी दी गई कि पन्ना तहसील अंतर्गत धरम सागर तालाब, सारंगधर मंदिर, बृहस्पति कुंड, शिव बाबा स्थल एवं केन नदी तट मड़ला में मकर संक्रांति मेला का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह गुनौर तहसील में जानकीरमण मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, बंधौरा एवं जलहरी मेला, देवेन्द्रनगर में मिढ़ासन नदी के तट पर एवं रूपझिर मेला, अमानगंज में हनुमान मंदिर द्वारी, बरबसपुरा मेला, सस्नदी संगम पण्डवन एवं गंगाझिरिया मेला, पवई तहसील में मां कलेही मंदिर के समीप पतने नदी तट पर, हनुमान भाटा, चांदनपुर एवं धौरमिला मेला, शाहनगर में गंगाझिरिया मेला बिसानी, रैपुरा तहसील में शिवजी का मेला नांदचांद एवं पटपरनाथ मेला, अजयगढ़ तहसील में अजयपाल किला, बरियारपुर डैम, इचैलिया मेला धरमपुर, टिकुरहा मेला धरमपुर एवं केवटपुर मेला तथा सिमरिया तहसील में जलखंडी, अमहा, नयागांव एवं कुटेश्वर में मेला लगेगा।

सरकार का नौकरी देने का वायदा खोखला, रोजगार कार्यालय बना शोपीस, नहीं दिला पाया नौकरी

आउटसोर्स कम्पनियों के माध्यम से हो रही भर्तियों में बेरोजगारों का हो रहा शोषण, सरकार का लाखों की भर्ती का चुनावी वायदा खोखला

नवभारत न्यूज

पन्ना 5 जनवरी, सरकारें चाहे जिस दल की हो खोखले वादे के अलावा कुछ नहीं करती हैं। यही हाल भाजपा सरकार का है पिछले 20 वर्षो के दौरान भाजपा का शासन प्रदेश में चल रहा है और हर पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के बेरोजगारों को लाखों की संख्या में रोजगार देने का चुनावी वादा किया गया था। जो पूर्णत: खोखला साबित हुआ।

आज लगभग समस्त विभागों की यह स्थिति है कि प्रत्येक विभाग में हर वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आधे पद खाली पडे हुए है। ऐसे में कैसे काम जनता के हो सकेंगे स्वमेव स्पष्ट है। बढ़ती बेरोजगारी एक बडी समस्या बनती जा रही है राज्य सरकार का रोजगार विभाग भी पूरी तरह से केवल कागजों तक सिमट कर रह गया है। जनप्रतिनिधियों को बेरोजगारी और रोजगार दिलाने का मुद्दा 5 साल में एक बार याद आता है। अलबत्ता पढे लिखे होनहार युवाओं के लिए अब सरकारी नौकरी एक सपने की की तरह हो चुकी है। ले देकर विभिन्न कंपनियों 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए भी मारामारी मची हुई है। सरकार द्वारा चलाई जा रहे रोजगार मेलों में सपने तो बहुत दिखाई जाते हैं लकिन असलियत यह है कि वहां 6 हजार से 10 हजार की नौकरी पन्ना से 1000 किमी. दूरी पर मिलती है। इन हालातों मे बेरोजगारों की मानसिक स्थिति क्या हो रही होगी स्वयं सोचनीय है।

गौरतलब है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोडने के लिए सरकार ने विभाग ही अलग बना रखा है लेकिन यह रोजगार विभाग भी युवाओं की अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पा रहा है प्रदेश के 15 जिलों में सरकार ने रोजगार कार्यालय बंद कर पीपीसी मॉडल पर प्लेसमेंट सेंटर खोला, लेकिन वह भी निर्धारित शर्तो के अनुसार काम नहीं कर पाए।

प्राइवेट कम्पनियों की प्रताड़ना से लौट रहे युवा

बीते कुछ वर्षो के अंतराल में प्राइवेट कंपनियां रोजगार देने के लिए रोजगार मेले में आती हैं। यहां तो प्रलोभन काफी दिए जाते हैं और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में रोजगार दिया जाता है हर साल बडी संख्या में युवा वापस लौट रहे हैं और उनका कहना होता है कि कम पैसे में अधिक कार्य कराया जाता है और कंपनी द्वारा प्रताडित भी किया किया जाता है कई मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई है दस वर्ष में रोजगार की स्थिति संभाग में प्रशासन द्वारा इस संबंध में जो आंकडे जारी किये गये हैं उसमें पन्ना की स्थिति बडी दयनीय हैं।